

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल द्वितीय अपील संख्या 617/2018

बलवंत सिंह पुत्र धनीराम, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़
जिला अलवर राजस्थान

-----अपीलकर्ता

बनाम

विजय सिंह पुत्र घीसाराम, निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर
राजस्थान

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री गजानंद यादव
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री गौरव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन

आदेश

प्रकाशनीय

31/01/2024

1. विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2 बहरोड़, अलवर द्वारा पारित सिविल अपील संख्या 88/2013 (01/2012) में दिनांक 01.02.2017 के निर्णय और डिक्री से व्यथित अपीलकर्ता वादी द्वारा तत्काल द्वितीय अपील प्रस्तुत की जाती है, जिसके द्वारा विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), बहरोड़, अलवर द्वारा पारित सिविल वाद संख्या 154/2009 में दिनांक 16.11.2011 के

निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर धारा 96 सीपीसी के तहत प्रथम सिविल अपील दायर की गई थी।

2. विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), बहरोड़ जिला अलवर ने अपीलार्थी-वादी द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद दिनांक 16.11.2011 को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर सिविल वाद संख्या 154/2009 को खारिज कर दिया है।

3. इस अपील के साथ, आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 सीपीसी के तहत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि वादी की जमीन पर अतिक्रमण की धमकी और बेदखली की आशंका के आधार पर, ट्रायल कोर्ट में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया गया था जिसमें वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत साक्ष्य पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने में विफल रहे हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत का मानना था कि वादी के दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज दायर नहीं किया गया इसलिए कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने दलील दी कि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए, अपीलकर्ता को कोई दस्तावेज दायर करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कानूनी स्थिति की गलत व्याख्या की है। उन्होंने आगे दलील दी कि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है उन्होंने यह भी कहा कि इस अपील को दायर करने में 579 दिनों की देरी हुई और देरी के कारणों को साबित करने के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन, इस दावे के समर्थन में

दस्तावेजों के साथ दायर किया गया है कि अपीलकर्ता दुर्घटना के कारण घायल हो गया और वह अस्पताल में भर्ती रहा तथा लंबे समय तक बिस्तर पर रहा, इसलिए देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाने में सक्षम है।

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का इस आधार पर विरोध किया कि द्वितीय अपील निचली अदालत के समवर्ती निष्कर्षों के आधार पर की गई है और द्वितीय अपील में निर्णय के लिए कोई विधि प्रश्न नहीं बनाया जा सकता, इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए कोई पर्याप्त आधार दिखाने में विफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित कानूनी दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए अपीलकर्ता को अतिरिक्त साक्ष्य का अवसर नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि अपील 01.02.2017 को खारिज कर दी गई थी और कथित दुर्घटना 07.10.2017 को हुई थी, लेकिन पूर्वोक्त दुर्घटना से कुछ दिन पहले और बाद में अपीलकर्ता द्वारा देरी के लिए माफी मांगने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताए गए थे।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

7. अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि 13.11.1997 से लगातार कब्जे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया गया था, लेकिन विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा 16.11.2011 को वाद खारिज कर दिया गया, हालाँकि अपीलकर्ता वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। उपरोक्त से व्यथित होकर, अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष सीपीसी की धारा

96 के अंतर्गत एक अपील दायर की गई, जिसे 01.02.2017 को खारिज कर दिया गया।

8. रिपोर्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि इस अपील में 579 दिन का विलंब हो चुका है, यद्यपि दुर्घटना के आधार पर विलंब को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है। चिकित्सा दस्तावेजों के अनुसार, पहला पर्चा 04.10.2017 का था। इसके बाद रिकॉर्ड पर एक और प्रमाण पत्र यह इंगित करने के लिए है कि 07.10.2017 से बलवंत सिंह आपातकालीन स्थिति में थे लेकिन शांति मुकुंद अस्पताल के अनुसार, उन्हें 11.10.2017 से 14.10.2017 तक भर्ती कराया गया था। यहां कोई अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है जो यह इंगित करता हो कि अपीलकर्ता 04.10.2017 से 14.10.2017 के अलावा किसी अन्य अवधि के लिए चिकित्सा उपचार में रहा। वर्तमान अपील 05.12.2018 को दायर की गई है जबकि आक्षेपित निर्णय 01.02.2017 को सुनाया गया था और एक प्रमाणित प्रति 06.02.2017 को प्राप्त की गई थी। विलम्ब की माफी के प्रयोजनार्थ अधिकतम अक्टूबर से दिसम्बर 2017 तक की अवधि पर विचार किया जा सकता है।

9. अपीलकर्ता को विलम्ब क्षमा के लिए पर्याप्त आधार दिखाना आवश्यक है, लेकिन यहाँ अपीलकर्ता अत्यधिक विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण बताने में विफल रहा है। जी. रामगौड़ा बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एआईआर 1987 एससी 897 में, यह माना गया था कि "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति का उदार अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय प्राप्त हो सके और सामान्यतः अपील दायर करने में विलम्ब के लिए या तो निष्क्रियता होती है या फिर सद्भावना की कमी होती है, जो विलम्ब क्षमा चाहने वाले पक्ष पर आरोपित की जा सकती है।

10. कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम काटिजी एआईआर 1987 एससी 1353 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:

1. सामान्यतः किसी वादी को देरी से अपील दायर करने से कोई लाभ नहीं होता।
2. विलंब को क्षमा करने से इनकार करने पर एक उचित मामले को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जा सकता है और न्याय का उद्देश्य विफल हो सकता है। इसके विपरीत, जब विलंब को क्षमा किया जाता है, तो सबसे अधिक यही हो सकता है कि पक्षकारों की सुनवाई के बाद मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाए।
3. "हर दिन की देरी की व्याख्या ज़रूरी है" का मतलब यह नहीं कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं? इस सिद्धांत को तर्कसंगत और व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
4. जब पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार एक दूसरे के विरुद्ध खड़े किए जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि दूसरा पक्ष यह दावा नहीं कर सकता कि गैर-जानबूझकर की गई देरी के कारण अन्याय होने का उसे अधिकार है।
5. यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि देरी जानबूझकर, या सदोष लापरवाही के कारण, या दुर्भावना के कारण हुई है। देरी करने से वादी को कोई लाभ नहीं होता। वास्तव में, वह एक गंभीर जोखिम उठाता है।
6. यह समझना होगा कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अन्याय को

दूर करने में सक्षम है और उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।

11. उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता अक्टूबर 2017 से पहले और दिसंबर 2017 के बाद अपील दायर न करने के लिए देरी का पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहा है, इसलिए मैं इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, इस प्रकार यह दूसरी अपील समय सीमा से वर्जित है और देरी की माफी के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

12. वाद 19.07.2009 को उपार्जित वाद हेतुक के आधार पर दायर किया गया था और उसके बाद यह दो वर्ष से अधिक समय तक निचली अदालत में लंबित रहा, लेकिन अपीलकर्ता के दावे के समर्थन में कोई भी दस्तावेज दाखिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार, प्रथम अपील 2012 में दायर की गई और फरवरी, 2017 में उसका निपटारा कर दिया गया, लेकिन इस अवधि के दौरान वादपत्र में किए गए कथनों के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जब अपील खारिज कर दी गई और द्वितीय अपील दायर की गई, तब अपीलकर्ता-वादी द्वारा आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया।

13. सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य लेने के आवेदन को अनुमति देने का सिद्धांत यह है कि किसी भी दस्तावेज या मौखिक रूप से अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन तभी अनुमति दी जा सकती है जब अपील दायर करने वाला पक्ष यह स्थापित/साबित करने में सक्षम हो कि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा जब ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का निपटारा कर दिया। हाल ही में संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड

राज्य (सिविल अपील संख्या 1760/2022) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के दायरे को समझाया है और यह निर्धारित किया है कि प्रावधान अपीलीय अदालत को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए. अंदिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार (2015) 17 एससीसी 713 और उत्तरादि मठ बनाम राघवेंद्र स्वामी मठ (2018) 10 एससीसी 484 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

14. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अभिलेखों में और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से भी कोई पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है, अतः आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेखों में दर्ज करने हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा, कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेखों में दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

15. धारा 100 सीपीसी के तहत तत्काल दूसरी अपील की जाती है और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

(1) इस संहिता के मूल भाग में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।

(2) एकपक्षीय रूप से पारित अपीलीय डिक्री के विरुद्ध इस धारा के अधीन अपील की जा सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में अंतर्वलित विधि के सारवान प्रश्न का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, वहां वह उस प्रश्न का निरूपण करेगा।

(5) अपील की सुनवाई इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी और अपील की सुनवाई के समय प्रत्यर्थी को यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात न्यायालय की, उसके द्वारा तैयार न किए गए किसी अन्य सारवान विधि प्रश्न पर अपील सुनने की शक्ति को, उसके कारणों को लेखबद्ध करके, छीनने वाली या न्यून करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर, विशेष रूप से सीपीसी की धारा 100 के आलोक में, विचार करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि अपील पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई ऐसा तात्त्विक विधि प्रश्न न हो जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता हो। यह न्यायालय सीपीसी की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तथ्यों के विशुद्ध प्रश्न में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सामान्यतः, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष और अपील खारिज करने की स्थिति में, यह न्यायालय तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि कोई तात्त्विक विधि प्रश्न न हो।

17. यह निर्धारित करने के लिए कि कोई प्रश्न विधि का सारवान प्रश्न है या नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा चुन्नीलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एआईआर 1962 एससी 1314 के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:

"हमारे विचार में, इस मामले में उठाया गया विधि का प्रश्न सारवान है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या यह पक्षकारों के अधिकारों को प्रत्यक्ष और सारवान रूप से प्रभावित करता है, और यदि ऐसा है तो क्या यह इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि यह इस न्यायालय, प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है, या यह कठिनाइयों से मुक्त नहीं है या वैकल्पिक विचारों पर चर्चा की मांग करता है। यदि प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है या प्रश्न के निर्धारण में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का मात्र प्रश्न है, या उठाया गया तर्क स्पष्ट रूप से बेतुका है, तो यह प्रश्न विधि का सारवान प्रश्न नहीं होगा।"

18. एम. एस. वी. राजा बनाम सीनी थेवर एआईआर 2001 एससी 3389 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि विधि के सारवान प्रश्न का निर्माण, द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा वास्तव में विचारित और विनिश्चित किए गए प्रश्नों के प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है, भले ही विधि के सारवान प्रश्न विशिष्ट रूप से और अलग से तैयार नहीं किए गए थे।

19. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश लतारुजी रामटेके बनाम सौ सुमाबाई पांडुरंग पेटकर एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 6070/2023,

एसएलपी(सी) संख्या 20183/2022 से शुरू, 21.09.2023 को तय) के मामले में सीपीसी की धारा 100 के दायरे पर विचार किया और कानून का सारांश इस प्रकार दिया:

13. धारा 100, सीपीसी पर न्यायशास्त्र समृद्ध और विविध है। इस न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में बार-बार उन आवश्यकताओं को निर्धारित, संक्षिप्त और स्पष्ट किया है जिनकी पूर्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए ताकि द्वितीय अपील, जैसा कि इसमें निर्धारित है, स्वीकार्य हो और उसके बाद उस पर निर्णय दिया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय के समक्ष ऐसे अनेक मामले दायर किए गए हैं जो इस प्रावधान के अनुप्रयोग पर आधारित हैं, हम इन सिद्धांतों को दोहराना आवश्यक समझते हैं।

13.1 इस धारा के अंतर्गत सबसे बुनियादी आवश्यकता "कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न" की उपस्थिति और उसका निर्माण है। दूसरे शब्दों में, इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए ऐसे प्रश्न का अस्तित्व अनिवार्य है।

13.2 इस धारा के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का वर्णन इस न्यायालय ने गुरदेव कौर बनाम काकी (2007) 1 एससीसी 546 (दो न्यायाधीशों की पीठ) में किया है, जिसमें कहा गया है कि 1976 के संशोधन के बाद, धारा 100 सीपीसी का दायरा काफी सीमित हो गया है और इसकी प्रकृति प्रतिबंधात्मक हो गई है। उच्च न्यायालय को धारा 100 सीपीसी के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार केवल उन्हीं मामलों में है जहाँ विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हों, जिन्हें अपील ज्ञापन में भी स्पष्ट रूप से तैयार/निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि:

"द्वितीय अपील के प्रवेश के समय, उच्च न्यायालय का यह परम कर्तव्य और दायित्व है कि वह विधि के सारवान प्रश्न

तैयार करे और उसके बाद ही उच्च न्यायालय को उन विधि के प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति है। संशोधित धारा में प्रयुक्त भाषा में विशेष रूप से "विधि का सारवान प्रश्न" जैसे शब्द शामिल हैं, जो विधायी मंशा का संकेत है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि विधायी मंशा बहुत स्पष्ट थी कि विधायिका कभी नहीं चाहती थी कि द्वितीय अपील "तथ्यों पर तीसरा परीक्षण" या "जुआ में एक और पासा" बन जाए। संशोधित धारा के अनुसार, संशोधन का मुख्य प्रभाव यह था:

- (i) उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील को तभी स्वीकार करना न्यायोचित होगा जब इसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न सम्मिलित हो;
- (ii) विधि का सारवान प्रश्न, ऐसे प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताना;
- (iii) अपील की सुनवाई से पहले विधि का सारवान प्रश्न तैयार करने का कर्तव्य उच्च न्यायालय पर डाला गया है;
- (iv) धारा का एक अन्य भाग यह है कि अपील केवल उसी प्रश्न पर सुनी जाएगी।"

रणधीर कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह एवं अन्य (2019) 17 एससीसी 71 में गुरदेव कौर (सुप्रा) का उल्लेख किया गया और उस पर भरोसा किया गया।

13.3 संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (2001) 3 एससीसी 179 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के सारवान प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिया था:

क) भूमि कानून या बाध्यकारी मिसाल द्वारा पहले से तय नहीं किया गया हो।

ख) मामले के निर्णय से संबंधित सामग्री; और (ग) उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया कोई नया मुद्दा

मामले से संबंधित नहीं है, जब तक कि वह मामले की जड़ तक न पहुँच जाए। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

केरल सरकार बनाम जोसेफ 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 961 और चंद्रभान बनाम सरस्वती 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1273 में ऐसे सिद्धांतों का पालन किया गया है

13.4 लॉरेंडर्स की कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रश्न(प्रश्नों) का निर्माण न करना "स्पष्ट रूप से अवैध" है। उमरखान बनाम बिमिलाबी (2011) 9 एससीसी 684 और शिव कोटेक्स बनाम तिरगुन ऑटो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2011) 9 एससीसी 678 में इस न्यायालय के निर्णय इस स्थिति को इंगित करते हैं।

14. उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर उसमें उठाए गए तर्कों के आलोक में दिया जाना चाहिए।

14.1 यदि न्यायालय का यह विचार है कि तैयार किए गए प्रश्न को परिवर्तित किया जाना है, हटाया जाना है या नया प्रश्न जोड़ा जाना है, तो न्यायालय को पक्षकारों को सुनना होगा।

14.2 उपरोक्त दोनों सिद्धांतों के लिए, गजराबा भीखुभा वढेर बनाम सुमारा उमर अमद (2020) 11 एससीसी 114 का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया गया था:

क) उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए विधि के मूल प्रश्न का उत्तर, कारण सहित, अवश्य दिया जाना चाहिए। उसका उत्तर दिए बिना अपील का निपटारा करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

(ख) यदि किसी प्रश्न को संशोधित, परिवर्तित या हटाने की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो उसके संबंध में पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

14.3 जब मामला स्वीकार कर लिया जाता है, किन्तु सुनवाई के दौरान जब यह पाया जाता है कि विचारणीय कोई विधि का सारवान प्रश्न नहीं उठता है, तो ऐसी बर्खास्तगी में कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए।

15. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम रूफ़ाइट (प्रा.) लिमिटेड (2009) 16 एससीसी 280 में यह टिप्पणी की गई थी:

"4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100(5) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है, जहाँ द्वितीय अपील के प्रतिवादी को "यह तर्क देने की अनुमति है कि मामले में ऐसा कोई प्रश्न शामिल नहीं है" अर्थात् पहले तैयार किए गए प्रश्न। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर द्वितीय अपील पर आदेश में, चाहे कितना भी संक्षेप में, यह इंगित किया जाना चाहिए कि पहले चरण में तैयार किए गए प्रश्न, अंतिम सुनवाई के चरण में, विधि के प्रश्न क्यों नहीं पाए गए।"

16. सामान्यतः, महत्वपूर्ण प्रश्न बाद में तैयार नहीं किए जाने चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो पक्षकारों को उनका सामना करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। यू.आर. विरुपाक्षप्पा बनाम सर्वमंगला (2019) 2 एससीसी 177 में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया:

"15. इसके अतिरिक्त, न्यायालय को सामान्यतः किसी भी महत्वपूर्ण विधि प्रश्न को बाद में बिना कोई कारण बताए और प्रतिवादियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना तैयार नहीं करना चाहिए। [देखें नुने प्रसाद बनाम नुने रामकृष्ण

[(2008) 8 एससीसी 258 : (2008) 10 स्केल 523] ; पंचुगोपाल बरुआ बनाम उमेश चंद्र गोस्वामी [(1997) 4 एससीसी 713] (एससीसी पैरा 8 और 9); और क्षितीश चंद्र पुरकैत बनाम संतोष कुमार पुरकैत [(1997) 5 एससीसी 438] (एससीसी पैरा 10 और 12)]।

16. हालाँकि, इस मामले में, उच्च न्यायालय ने खुली अदालत में फैसला सुनाते समय एक सारवान विधि प्रश्न तैयार किया। ऐसा सारवान विधि प्रश्न तैयार किए जाने से पहले, पक्षकारों को सूचित किया जाना चाहिए था। उन्हें इसका उत्तर देने का अवसर दिया जाना चाहिए था। हालाँकि न्यायालय के पास बाद के चरण में एक सारवान विधि प्रश्न तैयार करने का अपेक्षित अधिकार क्षेत्र है, जिसे द्वितीय अपील के स्वीकार किए जाने के समय तैयार नहीं किया गया था, फिर भी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के साथ संलग्न परंतुक में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक था।”

16.1 इस न्यायालय ने महबूब -उर- रहमान बनाम अहसानुल गनी, (2019) 19 एससीसी 415 में धारा 100(5) सीपीसी के आवेदन के संबंध में निम्नानुसार अवलोकन किया:

क) उपधारा (5) के परंतुक के अधीन यह नियम नहीं है कि किसी अन्य विधि के सारवान प्रश्न पर सुनवाई की जाए, चाहे वह प्रश्न कोई भी हो, जिससे धारा 100, सी.पी.सी. की अन्य अपेक्षाएं निरस्त हो जाएं।

(ख) अपवादात्मक मामलों में प्रावधान लागू होगा, जहां उच्च न्यायालय द्वारा कारण दर्ज किए जाने हैं।

16.2 यह भी माना गया है कि इस धारा का अनुप्रयोग केवल तभी होता है जब कुछ प्रश्न, जो विधि में सारवान हों, पहले से ही निर्धारित हों। (बी.सी. शिवशंकर बनाम बी.आर. नागराज) (2007) 15 एस.सी.सी. 387

16.3 प्रिवी काउंसिल, संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का गलत अनुप्रयोग, न तो विधि के सारवान प्रश्न के लिए योग्य होगा और न ही तथ्यों का गलत अनुप्रयोग।

16.4 यदि किसी मुद्दे पर, निचली अदालत साक्ष्य पर चर्चा करती है, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालती है, तो धारा 100, सीपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है। गोविंदभाई छोटाभाई पटेल बनाम पटेल रमनभाई माथुरभाई (2020) 16 एससीसी 255 का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

यह न्यायालय कौंडिबा दगाडु कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर (1999) 3 एससीसी 722, अवलोकन किया गया-

"6. यदि किसी विधि प्रश्न को सारवान प्रश्न कहा गया है और उसका निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय की किसी वृहद पीठ, प्रिवी काउंसिल, संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही हो चुका है, तो मामले के तथ्यों पर उसके केवल गलत प्रयोग को सारवान विधि प्रश्न नहीं माना जाएगा। जहाँ किसी विधि प्रश्न पर बहस नहीं की गई है या किसी तथ्यात्मक प्रारूप के अभाव में पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता पाया गया है, वहाँ किसी वादी को द्वितीय अपील में उस प्रश्न को सारवान विधि प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों या प्रविष्टियों के अर्थ और दस्तावेज की विषय-वस्तु का मूल्यांकन ही सारवान विधि प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता..."

16.5 असाधारण मामलों में तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की अनुमति है, अर्थात्, जब निष्कर्ष अस्वीकार्य या बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हो। इस न्यायालय ने दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली (2010) 12 एससीसी 740 में विभिन्न

अन्य मामलों का हवाला देते हुए यह निर्णय दिया:- क) उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना इस प्रकार स्वीकार्य नहीं है मानो वह प्रथम अपीलीय न्यायालय हो, जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हों।

ख) तथ्य की खोज को असाधारण परिस्थितियों में नियमितता के बजाय दुर्लभता के रूप में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

ग) द्वितीय अपील में साक्ष्य की जांच निषिद्ध नहीं है, लेकिन इसे उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

17. दूसरी अपील के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है। हमीदा बनाम मोहम्मद खलील (2001) 5 एससीसी 30 में यह टिप्पणी की गई थी।

7. ...यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय, धारा 100 सीपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल इस आधार पर तथ्यों के आधार पर निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को पलट नहीं सकता कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा पाए गए तथ्यों के आधार पर एक अन्य दृष्टिकोण संभव था।”

अवतार सिंह एवं अन्य बनाम बिमला देवी एवं अन्य (2021) 13 एससीसी 816 द्वारा इस स्थिति को दोहराया गया ।

17.1. ऐसे प्रतिबंधित आवेदन के मामले में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह "तीसरी अपील" का स्वरूप धारण न कर ले, एक आवश्यक पहलू यह है कि साक्ष्यों की सीमित समीक्षा की संभावना होती है और साथ ही, तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को पलटने पर प्रतिबंध होता है। हालाँकि, इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने नज़ीर मोहम्मद बनाम जे. कमला (2020) 19 एससीसी 57 में निम्नलिखित रूप में बताया है:

"33.4. सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यह कोई पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सुप्रसिद्ध अपवाद इस प्रकार हैं:

(i) निचली अदालतों ने भौतिक साक्ष्यों की अनदेखी की हो या बिना किसी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की हो; (ii) अदालतों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाले हों; या (iii) अदालतों ने सबूत का भार गलत तरीके से डाला हो। बिना किसी साक्ष्य के आधार पर लिया गया निर्णय केवल उन मामलों को संदर्भित नहीं करता जहाँ साक्ष्यों का पूर्ण अभाव हो, बल्कि उन मामलों को भी संदर्भित करता है जहाँ समग्र रूप से लिया गया साक्ष्य, निष्कर्ष का समर्थन करने में उचित रूप से सक्षम नहीं है।"

17.2 इसकी सीमा इस अवलोकन से रेखांकित की जा सकती है कि:

"32. द्वितीय अपील में, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विधि के सारवान प्रश्न तक सीमित होने के कारण, तथ्य का निष्कर्ष द्वितीय अपील में चुनौती के लिए खुला नहीं है, भले ही साक्ष्य की सराहना स्पष्ट रूप से गलत हो और तथ्य का निष्कर्ष गलत हो जैसा कि वी. रामचंद्र अय्यर बनाम रामलिंगम चेट्टियार [वि. रामचन्द्र अय्यर बनाम रामलिंगम चेट्टियार , एआईआर 1963 एससी 302] में कहा गया है। । उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक बिल्कुल नया मुद्दा, मामले में शामिल प्रश्न नहीं है, जब तक कि वह मामले की जड़ तक न जाए।"

20. माननीय न्यायालय ने चंद्रभान बनाम सरस्वती 2022 एससीसी ऑनलाइन (एससी) 1273 (22.09.2022 को निर्णीत) के मामले में सीपीसी की धारा 100 से संबंधित सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से संक्षेपित किया है:

"(i) निचली अदालतों ने भौतिक साक्ष्य को नजरअंदाज किया है या बिना किसी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की है;

(ii) न्यायालयों ने विधि को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाला है; या

(iii) अदालतों ने सबूत का भार गलत तरीके से डाला है।"

21. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी की धारा 100 से संबंधित सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया:

"(i) किसी दस्तावेज़ के वर्णन या विषय-वस्तु से तथ्य का अनुमान लगाना तथ्य का प्रश्न है। लेकिन किसी दस्तावेज़ के शब्दों का विधिक प्रभाव विधि का प्रश्न है। किसी दस्तावेज़ की रचना, जिसमें विधि के किसी सिद्धांत का अनुप्रयोग शामिल हो, भी विधि का प्रश्न है। इसलिए, जब किसी दस्तावेज़ की गलत रचना होती है या दस्तावेज़ की व्याख्या करते समय विधि के किसी सिद्धांत का गलत अनुप्रयोग होता है, तो यह विधि का प्रश्न उत्पन्न करता है।"

(ii) न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मामला विधि का एक सारवान प्रश्न है, न कि केवल विधि का प्रश्न। मामले के निर्णय पर प्रभाव डालने वाला विधि का प्रश्न (अर्थात, ऐसा प्रश्न, जिसका उत्तर वाद के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता हो) विधि का एक सारवान प्रश्न होगा, यदि वह विधि के किसी विशिष्ट प्रावधान या बाध्यकारी पूर्वोदाहरणों से उत्पन्न स्थापित विधिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है और उसमें कोई विवादास्पद विधिक मुद्दा शामिल है।

(iii) विधि का सारवान प्रश्न विपरीत स्थिति में भी उठेगा, जहां विधिक स्थिति स्पष्ट है, या तो विधि के स्पष्ट प्रावधानों के कारण या बाध्यकारी उदाहरणों के कारण, लेकिन निचली अदालत ने मामले का निर्णय या तो ऐसे विधिक सिद्धांत की अनदेखी करते हुए या उसके विपरीत कार्य करते हुए किया है।

(iv) दूसरे प्रकार के मामलों में, विधि का सारवान प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि विधि अभी भी बहस योग्य है, बल्कि इसलिए उठता है कि किसी सारवान प्रश्न पर दिया गया निर्णय विधि की स्थापित स्थिति का उल्लंघन करता है।

(v) सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय निचली अदालतों द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यह पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सुप्रसिद्ध अपवाद इस प्रकार हैं:

(क) निचली अदालतों ने भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की है या बिना किसी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की है;

(ख) न्यायालयों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाला है; या

(ग) न्यायालयों ने सबूत का भार गलत तरीके से डाला है।

(vi) जब न्यायालय "बिना साक्ष्य के आधार पर निर्णय" का उल्लेख करता है, तो वह न केवल उन मामलों को संदर्भित करता है जहां साक्ष्य का पूर्ण अभाव है, बल्कि किसी भी मामले को संदर्भित करता है, जहां समग्र रूप से लिया गया साक्ष्य, निष्कर्ष का समर्थन करने में उचित रूप से सक्षम नहीं है।"

22. विद्वान विचारण न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों और अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने पर विचार करते हुए, विशेष रूप से जिसमें कोई विकृति या अवैधता नहीं पाई गई, मेरा यह सुविचारित मत है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कोई भी विधिक प्रश्न, जिसके लिए न्यायनिर्णयन की आवश्यकता हो, तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।

23. उपरोक्त के मद्देनजर, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन, आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत आवेदन और दूसरी अपील को खारिज कर दिया गया है।

24. विविध आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा हो जाता है।

(अशोक कुमार जैन),जे

प्रीति वलेचा /59

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी